(b) Does not arise.

(c) According to legal advice it would not be constitutionally permissible to provide enhanced age-limit for women only on the ground of sex.

New Multinational Drug Companies in the country

*343. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of Multinational Drug Companies which have started operating in the country after the announcement of liberalised financial policy;

(b) the number of licences issued till date for manufacture of drugs or for enhancing the existing manufacturing capacities in respect of each company/ drug etc; and

(c) what steps Government have taken for indigenous production/research and development in various systems of medicines to save the out flow of foreign exchange?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) and (b) While no new multinational drug company has started operating in the country after the announcement of the liberalised industrial policy, 30 industrial approvals including letters of intent have been issued to the existing companies for manufacture of drugs as new articles or for enhancing existing capacities.

(c) Various incentives like broad banding, regularisation of production, re-endorsement of capacities, ratio parameters etc. are available in the existing Drug Policy, 1986, which are aimed towards increasing indigenous production. There are several Central Research Laboratories engaged in R & D activities in various systems of medicines. Under Drug Policy'86 the following incentives for R & D are available to pharmaceutical industry:

(i) Expenditure incurred on R & D is taken into account while determining cost of production of bulk drugs under price control.

(ii) A company is allowed to retain 50% of the reduction in price of price controlled bulk drug achieved through R & D efforts.

(iii) if a company develops a process for a bulk drug through its own R & D efforts or through National Laboratories, from basic stage, and which is ~~significantly~~ different from existing processes and results in cost-effective production, exemption from price control is *available for a period not exceeding 5* years from the date of commercial production.

(iv) Higher profitability ceiling for units engaged in approved research and development work relating to new drugs.

(v) As in case of R & D work in other Sectors of Industry, Pharmaceutical Sector also enjoys incentives and support measures such as Income Tax relief, Accelerated Depreciation allowance, Import facility etc.

To encourage R & D activity in Pharmaceutical Industry a number of further suggestions are under examination as part of the Review of the Drug Policy, the background note in regard to which has already been placed in both the Houses of Parliament for obtainting the views of Members of Parliament before taking necessary final decison in the matter.

सरकारी क्षेत्र के एककों का घाटा

*346. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के एककों के घाटे को कम करने के लिए सरकार इन एककों को सुदृढ़ बनाने के किन्हीं कदमों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एककों की प्रबंध-व्यवस्था में भ्रष्टाचार रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) केवल वर्ष 1990-91 तक की ही जानकारी उपलब्ध है और उक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले उद्यमों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि 109 उद्यमों ने कुल 3046 करोड़ रुपये का घाटा उठाया। इनमें से 54 विनिर्माणकारी उद्यमों को चिरकालिक रुग्ण उद्यम माना गया है और इन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा जाना है ताकि इनके नवीकरण/पुनर्वास की योजनाएं बनाई जा सके। अन्य 13 उद्यम ऐसे हैं जो चिरकालिक रुग्ण तो हैं परन्तु उन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को नहीं सौंपा जाना है। इन उद्यमों के लिए नवीकरण योजना का निर्माण प्रशासनिक मंत्रालयों और संबद्ध प्रबंधनों द्वारा किया जाना है। सरकार घाटा उठाने वाले सभी उद्यमों के कार्य-निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा कर रही है। और उद्यम-विशेष की आवश्यकता के अनुसार सुधारात्मक कार्य किए जा रहे हैं।

(ग) विविध सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यमों में सतर्कता तंत्र जैसी सांस्थानिक व्यवस्था पहले से की जा चुकी है और इन्हें उद्यमों के प्रबंधन में भ्रष्टाचार और कदाचारों के मामलों, यदि कोई हो, को रोकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये कृतिक बल

*347. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये एक कृतिक बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कृतिक बल को क्या-क्या जिम्मेदारियां और कौन-कौन से क्षेत्र सौंपे गये हैं;

(ग) क्या इस कृतिक बल द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या कृतिक बल ने सरकार को कोई प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गयी हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

Reciprocity regarding visa fees with the foreign missions

*348. CHOWDHRY HARI SINGH:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any reciprocity is maintained between Indian Missions abroad and the Foreign Missions in India with regard to collection of visa fees;

(b) if so, what are the broad features of the systems followed and the details of reciprocity maintained with different countries; and

(c) whether in case of rejection of applications certain foreign missions do not refund the full fee charged in advance, if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R.L. BHATIA): (a) and (b) With effect from 12.12.91 a uniform visa fee schedule has been introduced applicable to all foreign nationals with the exception of those countries with which there are bilateral arrangements governing visas.

(c) The information is being collected.

*349. *[Transferred to 22nd December, 1992].*

गुजरात में फालतू भूमि का वितरण

*350. **श्री राम सिंह राठवा:**
श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में फालतू भूमि का वितरण कार्य अदालती मुकदमों के कारण सम्पन्न नहीं हो पा रहा है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार को